e: Need to conduct an inquiry into the alleged irregularities in procurement of wheat through the procurement centres and inordinate delay in payment of Minimum Support Price to farmers in Hoshangabad Parliamentary Constituency of Madhya Pradesh

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र होशंगाबाद के होशंगाबाद जिले में वÂाऩ 2011 में जिला प्रशासन द्वारा 141 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 7,31,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। जिले के सात विकास खंडों में उपार्जित गेहूं का प्रशासन के मुताबिक सम्पूर्ण संग्रहण वेयरहाउस, कवर गोदाम, अस्थाई कैम्पों एवं स्थाई मंडी बोर्ड के कैंपों में कुल 5,02,180 मीट्रिक टन गेहूं का संग्रहण किया गया था। इस गेहूं के परिवहन में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है। होशंगाबाद जिले में जितने भी गेहूं का परिवहन किया गया है, उसमें से लगभग 200 ट्रक गेंहू गायब है।

इस संबंध में समिति प्रबंधकों द्वारा थानों में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। इससे सात करोड़ रुपए की सीधी चपत केंद्र सरकार को जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई है। आरटीओ जब इन वाहनों का अधिग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया और ब्लैक लिस्टेड ट्रंसपोर्टरों को पुनः परिवहन का काम दे दिया, जिससे वे इतना बड़ा घोटाला करने में कामयाब हुए।

प्रशासन ने स्वीकार किया है कि पिछले वÂाऩ पांच लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वÂाऩ दोगुना गेहूं उपार्जित हुआ है। अच्छी भंडारण व्यवस्था के अभाव में गेहूं बंद और खुले स्थानों पर ठीक ढंग से नहीं रखा गया था, फिर भी इस वÂाऩ 7,31,000 मीट्रिक टन गेहूं क्यों खरीदा गया, जबकि इसके रख-रखाव की क्षमता ही नहीं है। इस मामले में केन्द्र सरकार ने राज्य शासन को सख्त निर्देश भी जारी किए थे कि भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था होने पर ही गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाए।

सभापति जी, मैं इस सदन में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से हजारों क्विंटल गेहूं मैदानों में बनाए गए कैंपों में लाखों रुपए की खरीदी गई घटिया पॉलिथीन की वजह से सड़ गया है। गेहूं की उपार्जन केन्द्रों पर किसानों को जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी थीं, वे भी नहीं कराई गई हैं। आज भी सैंकड़ों किसान ऐसे हैं, जिन्हें अपनी बेची फसल का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। किसान अपनी फसल का मूल्य लेने के लिए बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले की जांच कराई जाए एवम् इस वÂाऩ जो गेहूं की खरीद होगी, उसमें पारदर्शिता रहे, किसानों की मदद हो, ऐसी व्यवस्था की जाए।